P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-12*August- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता एवं भारतीय हितों पर प्रभाव : एक विश्लेषण

वीरेन्द्र चावरे
सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला,
विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन (म.प्र.)

सारांश

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता हैं जिसके अंतर्गत चीन व पाकिस्तान आर्थिक सहयोग तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की दिशा में कार्य कर रहें हैं। CPEC में दक्षिण एशिया की भू–राजनीतिक परिस्थितियों को पुनः अपने अनुसार करने की क्षमता हैं। CPEC के भारतीय विवादित क्षेत्र से निकलने के कारण भारत, वर्तमान में चीन–पाकिस्तान की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा नहीं हैं। भारत, चीन और पाकिस्तान के मध्य कुछ क्षेत्रीय विवादों का समाधान होना अभी शेष हैं। हालांकि, भारत और चीन के मध्य निरंतर क्षेत्रीय गतिशीलता तथा द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुई हैं। चीन द्वारा प्रस्तावित CPEC भारत–पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को पुर्नजीवित करने के प्रयासों के लिए एक अच्छा विकल्प हैं प्रस्तुत करता हैं। भारत व पाकिस्तान में आपसी विश्वास कायम हो जाये तो CPEC, भारत और पाकिस्तान के मध्य शांति प्रयासों और आर्थिक विकास तथा दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हैं।

पाकिस्तान इस परियोजना के पूर्ण होने पर उच्च आर्थिक विकास तथा दक्षिण एशिया में भारत के साथ शक्ति संतुलन को प्राप्त कर लेगा क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर में चीनी सेना की उपथिति भारत को पाकिस्तान पर सीधे कार्यवाही करने से रोक सकती हैं।

आर्थिक विकास हेतु अन्य दक्षिण एशियाई देश चीन को निवेश तथा CPEC के विस्तार के लिए आकर्षित कर सकते हैं। दक्षिण एशिया में शांति की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक की भारत व पाकिस्तान के आपसी मुद्दों का कोई हल नहीं होता। अमेरिका और भारत के कूटनीतिक संबंधों के चलते अब ये और अधिक कठिन हो गया हैं क्योंकि अमेरिका ने दक्षिण एशिया के लिए विशेष रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए नई रणनीति का खुलासा कर दिया हैं। अमेरिका, दक्षिण एशिया में भारत को एक सहयोगी तथा पाकिस्तान को एक समस्या के रूप में देख रहा हैं इसलिये अमेरिका ने अफगानिस्तान के आर्थिक विकास के लिए सहायता करने की जिम्मेदारी भारत को दी हैं। इसलिए भारत–अमेरिका–अफगानिस्तान और चीन–पाकिस्तान गठजोड़ एक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता के लिए समस्याऐं उत्पन्न कर सकती हैं।

मुख्य शब्द : CPEC, भारत, चीन, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया, अमेरिका।

प्रस्तावना

विगत कुछ वर्षो से CPEC दक्षिण एशिया और पाकिस्तान के साथ–साथ पूरी दुनिया में बहस का विषय हैं। दक्षिण एशियाई देश CPEC को आर्थिक विकास के अवसर तथा अपने विरूद्ध गठबंधन दोनों के रूप में देखते हैं। विश्व में CPEC पर भिन्न–भिन्न राय हैं। इस शोध पत्र में सभी धारणाओं को ध्यान में रखते हुए तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया हैं।

पिछले चार दशकों के दौरान चीन के सतत् विकास ने उसे विश्व अर्थव्यवस्था में एक विशेष स्थान प्रदान किया हैं। 1990 के दशक में चीन ने अपनी भूमिका को पुनः परिभाषित कर दिया था। आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध के चीन को नए वैश्विक परिदृश्य के अनुसार रणनीतियां बनाने का समय मिला। इस दशक में दुनिया आतंकवाद तथा वित्तीय संकट से जूझ रही थी, लेकिन इसी दौरान चीन ने अपने व्यापार में वृद्धि करते हुए मजबूती के साथ विश्व में नई पहचान बनाई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार दुनिया को रचनात्मक रूप से जुड़ने की पहल की।[1] इसी रचनात्मक जुड़ाव के अपने एजेंडे

पर चलते हुए शी जिनपिंग ने दक्षिण एशियाई देशों का दौरा किया और उन सभी दक्षिण एशियाई देशों के लिए बड़े निवेश और व्यापार वृद्धि कार्यक्रम की घोषणा की।

हाल के कुछ वर्षो में आर्थिक गलियारे क्षेत्रीय सहयोग और विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं। चीन के ग्रेटर मेकांग उप–क्षेत्र (जीएमएस) के आर्थिक गलियारे के एकीकरण के सफल होने के बाद से एशिया के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की पहल को बढ़ावा मिल रहा हैं ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को अधिक विकसित औद्योगिक केन्द्रों के साथ जोड़कर क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सकें।

इस संबंध में दक्षिण एशिया में दो आर्थिक गलियारे बनाने का प्रस्ताव आया। पहला महत्वपूर्ण प्रस्ताव 2013 में चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा (19–22 मई 2013) के दौरान ली केकियांग ने चीन के युन्नान प्रांत को आर्थिक गलियारे के द्वारा बीसीआईएम (बांग्लादेश–चीन–भारत–म्यांमार) से जोड़ने की पहल की। दूसरा महत्वपूर्ण कदम चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग की 22 से 23 मई 2013 की पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान चीनी प्रधानमंत्री ने चीन के झिंजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के काश्गर को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने का प्रस्ताव दिया और इस प्रकार 2013 में चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की नींव पड़ी।[2]

अध्ययन के उद्देश्य

1. चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव तथा इसके प्राप्त लाभ का विश्लेषण करना।
2. चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से उत्पन्न चुनौतियों के संबंध में भारतीय हितों की समीक्षा करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध–पत्र में दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता पर चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के प्रभाव का विश्लेषण, भारतीय हितों के संदर्भ में किया गया हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्दति का उपयोग किया गया है। इसमें विषय से संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, लेख–आलेख तथा वेबसाईट्स आदि स्त्रोंतो से प्राप्त अध्ययन सामग्री का उपयोग अध्ययन में किया गया हैं।

साहित्यावलोकन

एंड्रयू स्माल ने अपनी पुस्तक "द चाईना–पाकिस्तान एक्सिस : एशियाज न्यू जियो–पॉलिटिक्स" 2015 में बताया कि किस प्रकार बीजिंग और इस्लामाबाद इस गलियारे के माध्यम से दक्षिण एशिया के केन्द्र बिन्दु बन जायेंगे। इसके साथ ही दक्षिण एशिया तथा अफगानिस्तान में अमेरिका के प्रभाव एवं भारत की बढ़ती भूमिका तथा आतंकवाद, क्षेत्रीय स्थिरता व परमाणु हथियार के साथ ही पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला हैं।[3]

उरोज रिज ने अपनी पुस्तक "सीपेक चाईना–पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर" 2017 में चीन–पाक के संबंधों के इतिहास के अंतर्गत इस आर्थिक गलियारे की पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया हैं। इसके साथ ही *रिज* ने चीन–पाक के आर्थिक गलियारे से दक्षिण एशियाई देशों को होने वाले दूरगामी लाभ तथा हानियों का विश्लेषण करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता को बनाये रखने को एक चुनौती माना हैं।[4]

अर्चना राठौर ने अपनी पुस्तक "चाईना–पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (सीपेक)" 2017 में चीन–पाक के आर्थिक गलियारे से दक्षिण एशिया और यूरोपीय देशों को होने वाले लाभ तथा चीन की विस्तारवादी नीति का विश्लेषण इससे भारत के लिए उत्पन्न होने वाली चुनौतियों तथा इस गलियारे की सुरक्षा समस्या पर भी प्रकाश डालने के साथ ही दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का भी विश्लेषण किया हैं।[5]

चीन वर्तमान में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। चीन ने पांच वर्ष पूर्व आर्थिक महत्व की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को घोषित किया जिसमें पहली "सिल्क रोड़" तथा दूसरी "सामुद्रिक रेशम मार्ग"। इन दोनों परियोजनाओं को संयुक्त रूप से "वन बेल्ट, वन रोड़" यानी ओ.बी.ओ.आर. के नाम से जाना जाता हैं। चीनी आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार विगत कुछ वर्षो से चीन ने अपनी औद्योगिक उत्पादन क्षमता बढ़ाई हैं जिससे उसे नए बाजार ढूंढने की आवश्यकता हैं ताकि वह अपनी उत्पादित वस्तुओं को अन्य बाजारों तक पहुंचाकर विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकें।

चीन के लिए CPEC का महत्व

CPEC दक्षिण–मध्य–पश्चिम एशिया में चीनी विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इसके अंतर्गत चीन अपने आर्थिक एकीकरण की पहल का विस्तार करना चाहता हैं। चीनी विशेषज्ञों का मत हैं कि CPEC क्षेत्रीय समृद्धि और रचनात्मक जुड़ाव के उद्देश्य से पूर्ण रूप से एक आर्थिक पहल हैं। इसका उद्देश्य भारत को घेरना नहीं हैं और ना ही भारत के विरूद्ध चीन–पाकिस्तान गठजोड़ हैं। CPEC का उद्देश्य पाकिस्तान की सुरक्षा, रोजगार और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि करना हैं।[6] चीन चाहता हैं कि भारत भी CPEC का हिस्सा बनें, क्योंकि CPEC में भारत की उपस्थिति पाकिस्तान के असहज क्षेत्रों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।[7]

चीन अपनी तेल आवश्यकता की पूर्ति हेतु 60 प्रतिशत तेल पश्चिम एशिया से आयात करता हैं यह तेल मलक्का जलडमरूमध्य के रास्ते चीन पहुँचता हैं जिसमें भू–गर्भीय अनिश्चितताओं और समुद्री डाकुओं की चुनौती भी हैं। ग्वादर से काराकोरम तक की पाईपलाईन के माध्यम से आसानी से चीन बिना किसी समस्या के कम धन व समय खर्च किये अपनी तेल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा।

चीन अपने रचनात्मक जुड़ाव एजेंडे के अंतर्गत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा दक्षिण–मध्य–पश्चिम एशियाई देशों के मध्य घनिष्ठ संबंध और आर्थिक विकास में सहगोग कर रहा हैं। चीन भौगोलिक निकटता के कारण अपने पश्चिमी क्षेत्रों के विकास तथा अपनी पहुँच दक्षिण–मध्य–पश्चिम एशिया तक बढ़ाने के लिए CPEC की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

CPEC 46 अरब डॉलर की परियोजना हैं जिसकी लागत वर्तमान में 57 अरब डॉलर हो गई हैं।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-12*August- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

पाकिस्तान एक अर्थशास्त्री के अनुसार अगले 30 वर्षो में यह लागत 90 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगी। पाकिस्तान के विपक्ष के नेता CPEC को एक और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दे रहे हैं लेकिन इन आलोचनाओं का इस परियोजना पर कोई प्रभाव पड़ता अभी तो नहीं दिख रहा हैं।

पाकिस्तान के लिए CPEC का महत्व

पाकिस्तान का मानना हैं कि CPEC पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ–साथ दक्षिण एशिया में उसकी स्थिति को रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से गेमचेंजर माना जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान के ऊर्जा संकट के समाधान हेतु CPEC के अंतर्गत विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से 10,400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।

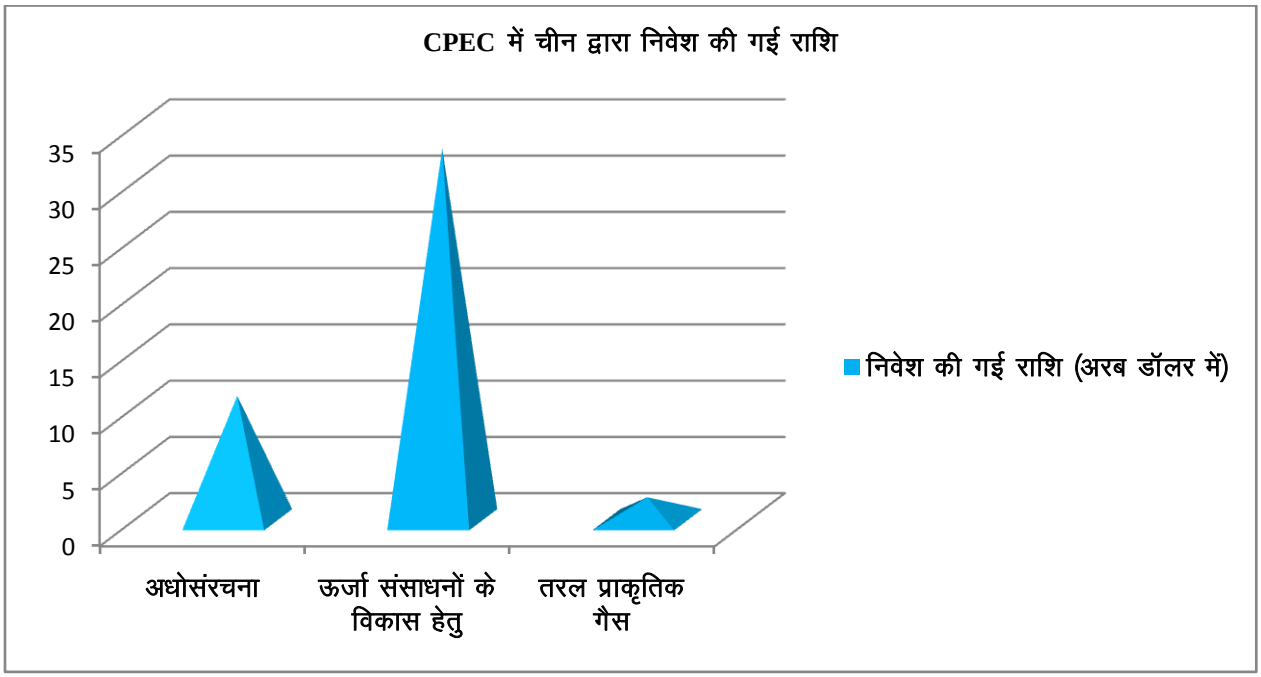

Source : Hamzah Rifaat & Tridivesh Singh Maini "The China-Pakistan Economic Corridor" Strategic Rationales, External Perspectives, and Challenges to Effective Implementation, Stimson Cnetre Washington DC, 2016

पाकिस्तान को इस परियोजना से यह उम्मीद हैं कि यह उसकी विकास दर को 7 प्रतिशत करने सफल होगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इस परियोजना का विरोध लगातार जारी हैं।

CPEC और भारत–चीन संबंध

भारत दक्षिण एशिया का प्रमुख देश हैं जो इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि पिछले दो दशकों में भारत–चीन संबंधों को देखे तो वे जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयागी हैं। दोनों देशों के मध्य 100 अरब डॉलर का व्यापार होता हैं जो दिनो दिन बढ़ रहा हैं। पाकिस्तान से निकटता के चलते भारत के साथ चीन के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं कि आपस में छोटे–छोटे मुद्दों पर टकराव ना हो।[7] CPEC को लेकर भारतीय राजनेता इस बात से भी चिंतित हैं चीन, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। इसके दो उदाहरण हैं पहला, चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकी मसूद अजहर के पक्ष में खड़े होकर भारतीय प्रयासों को बार–बार प्रभावित किया गया जबकि अन्य सदस्य देशों ने भारत का समर्थन किया। चीन द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादी के पक्ष में किये जा रहे प्रयासों के संबंध में भारत की विदेश मंत्री ने रूस–भारत–चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के मुद्दें पर चीन द्वारा अपनाये जा रहे दोहरे रवैये की आलोचना की। सुषमा स्वराज ने चीन के रवैये के संदर्भ में कहा कि यदि हम ऐसे ही आतंकवाद के विरूद्ध दोहरा रवैया अपनायेंगे तो एक दिन ना केवल आतंकवाद से प्रभावित देश वरन् अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।[9]

चीन भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारतीय हितों को प्रभावित कर रहा हैं। चीन लगातार परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत का विरोध करता रहा हैं। चीन का मानना हैं कि भारत के साथ–साथ पाकिस्तान को भी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनाया जाना चाहिए।[10] भारत सरकार ने समय–समय पर CPEC के लिए चीन के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया हैं। भारतीय दृष्टिकोण CPEC को प्रभावित करता हैं और भविष्य में भी यह भारत से प्रभावित होता रहेगा। CPEC के माध्यम से भारत मध्य व पश्चिम एशिया तथा यूरोप के बाजारों तक अपनी पहुँच बढ़ा सकता हैं।[11] वर्तमान में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया हैं जो मध्य व पश्चिम एशिया में उसकी भविष्य की संभावना को मजबूत करता हैं।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-12*August- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

CPEC और भारत–पाकिस्तान संबंध

CPEC उत्तरी पाकिस्तान के पाक–अधिकृत कश्मीर क्षेत्र से गुजरता हैं जो भारत–पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र हैं। पाकिस्तान ने 1947 से इस पर अनाधिकृत रूप से नियंत्रण किया हुआ हैं। गिलगित–बाल्टिस्तान जो पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, को अपना पांचवा राज्य बनाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को मजबूर किया है। क्योंकि चीन भारत–पाकिस्तान के मुद्दों पर सीधे हस्तक्षेप से बचना चाहता हैं।

CPEC के पूर्ण हो जाने के बाद पाक–अधिकृत कश्मीर के गिलगित–बाल्टिसतान में पाकिस्तान संवैधानिक स्थिति और चीन–भारत–पाकिस्तान के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। जहां एक ओर CPEC से पाकिस्तान में सकारात्मक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन होंगे वहीं दूसरी ओर भारत की मध्य व पश्चिम एशिया तथा यूरोप के बाजारों तक पहुँचने की संभावनाओं को प्रभावित करेगा।

CPEC की पूर्ण सफलता तथा चीन के सहयोग से आर्थिक रूप से सक्षम पाकिस्तान को भारत के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में रूचि नहीं रहेगी। वर्तमान में भारत में घट रही पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी घटनाओं के बावजूद भी दोनों देशों के मध्य वाघा–अटारी सीमा से द्विपक्षीय व्यापार 2 अरब डॉलर से ऊपर रहा हैं।[12]

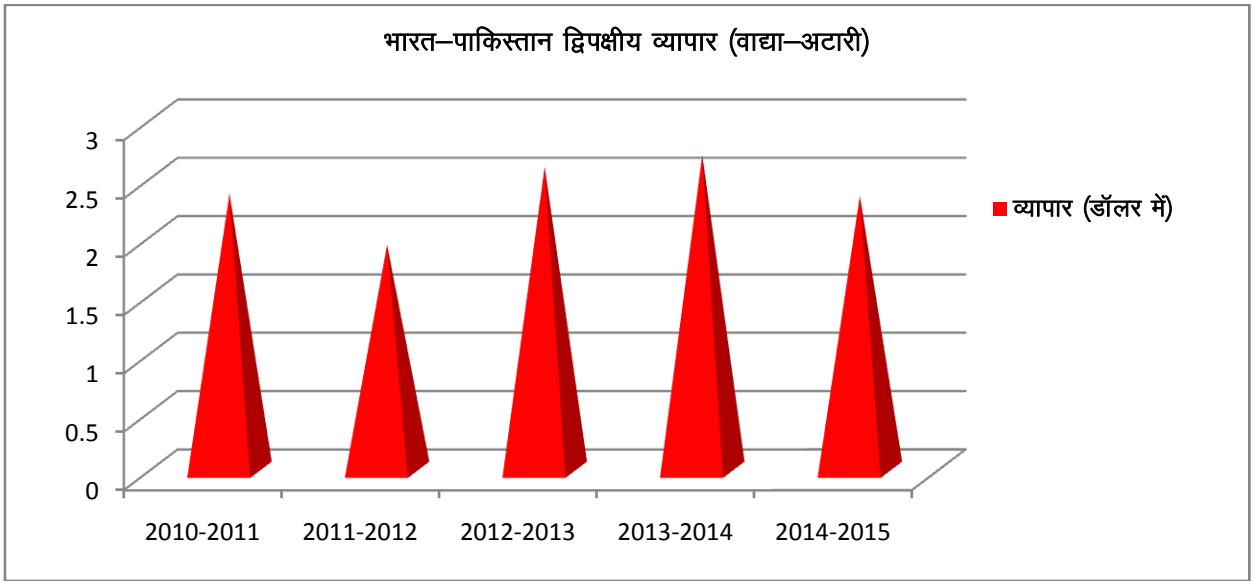

Source: Ministry of Commerce (Department of Commerce, Export Import Data Bank), Government of India. http://commerce.nic.in/eidb/iecnt.asp.

दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता और CPEC

चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा दोनों देशों के मध्य एक व्यापक आर्थिक समझौता हैं। यह ना केवल चीन और पाकिस्तान के मध्य आर्थिक और सामरिक उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, बल्कि ये दक्षिण–मध्य–पश्चिम एशिया को भी आर्थिक एकीकरण के सूत्र में बांधने का कार्य करेगा। हालांकि CPEC कुछ क्षेत्रीय देशों के लिए भयानक सपने की तरह हैं तथा यह परियोजना अन्य दक्षिण एशियाई देशों व्यापारिक व रणनीतिक रूप से प्रभावित करेगी जो कि दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती हैं।

सार्क और CPEC

भारत और पाकिस्तान के मध्य जटिल संबंधों के कारण तथा दक्षिण एशिया में राजनीतिक मतभेदों तथा सामाजिक–धार्मिक जटिलताओं के कारण क्षेत्रवाद दक्षिण एशिया में नहीं पनप पाया। भारत व पाकिस्तान के मतभेदों के कारण सार्क ने भी अपनी सार्थकता खो दी हैं। इन मतभेदों ने सार्क देशों के हितों को प्रभावित किया हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि अन्य सार्क देशों ने द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय सहयोग हेतु अन्य क्षेत्रीय संगठनों की ओर रूख किया हैं। भारत व पाकिस्तान के जटिल संबंधों लाभ चीन ने उठाते हुए सार्क देशों में विशेष रूचि ली हैं तथा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश तथा मालदीव में कई परियोजनाओं में निवेश हेतु पहल की हैं।[13]

अमेरिकी–चीनी सामरिक प्रतिद्वंद्विता

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अमेरिकी–चीन प्रतिद्वंद्विता एक अवरोध हैं। एक ओर अमेरिका दक्षिण एशियाई नीति शांतिपूर्ण भारत–पाकिस्तान संबंधों पर केन्द्रित हैं वहीं दूसरी ओर चीन केवल अपने उत्पादों को बाजार दक्षिण–मध्य एशिया में उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक एकीकरण के मार्ग पर चल रहा हैं। अमेरिका चीन को आर्थिक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता हैं जिसके कारण वह समय–समय पर दक्षिण एशियाई देशों को चीन की विस्तारवादी नीति से सावधान करता रहा हैं।[14] अमेरिका के चीन–पाकिस्तान से खराब संबंधों के बावजूद यदि CPEC पाकिस्तान को आर्थिक रूप से उन्नत तथा दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ पाया तो यह अमेरिकी नीति के अनुकूल होगा।

अमेरिका दक्षिण एशिया में CPEC के अंतर्गत चीनी निवेश को दक्षिण एशिया की स्थिरता में खतरे के रूप में देखता हैं। 2016 में आई पेंटागन रिपोर्ट में यह आशंका व्यक्त की गई की चीन ग्वादर में अतिरिक्त नौसैनिक अड्डा स्थापित करेगा।[15]

भारत–अमेरिकी रणनीतिक गठजोड़

वर्तमान में भारत और अमेरिकी के संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। दोनों देशों ने व्यापारिक संबंधों से आगे बढ़ते हुए कूटनीतिक तथा रक्षा संबंध स्थापित कर लिए हैं। विशेषज्ञों का मानना हैं कि भारत–अमेरिकी कूटनीतिक संबंधों का प्रारंभ 2006 में दोंनों देशों के मध्य हुए 123 परमाणु समझौते से हुए हैं। इस समझौते के बाद से ही अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन कर रहा हैं।[16]

अमेरिका की ट्रंप सरकार ने हाल ही दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अपनी नई रणनीति की घोषणा की हैं जिसमें उसका मुख्य केन्द्रबिन्दु अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैं। इस अमेरिकी रणनीति में उसके सैन्य बलों की अफगानिस्तान से वापसी मुख्य मुद्दा हैं। सैन्य बलों की वापसी से पहले अमेरिका चाहता हैं कि अफगानिस्तान के आंतरिक हालात स्थिर हो जाये इसके लिए वह भारत से यह अपेक्षा करता हैं कि वह अफगानिस्तान में दक्षिण एशिया में शांति की स्थापना हेतु मुख्य भूमिका निभाये।

अफगानिस्तान के साथ–साथ अमेरिका पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों के विरूद्ध भी अपनी रणनीति को स्पष्ट किया हैं। भारत भी इस मुद्दें को वैश्विक मंचों पर लगातार उठाता रहा हैं कि वह पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से पीड़ित हैं और दुनिया को इस पर ध्यान देते हुए आतंकवाद के विनाश हेतु अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। इस मुद्दें अमेरिका भारत का समर्थन करता हैं किन्तु दूसरी ओर चीन आतंकवाद के मुद्दें पर पाकिस्तान का समर्थन करता आ रहा हैं जो की दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं।

ग्वादर बंदरगाह पर चीनी नियंत्रण

चीन ग्वादर बंदरगाह के गहरे समुद्र में अपनी नौसेना के लिए एक शिपयार्ड का निर्माण करेगा। अपनी भू–राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहा हैं कि चीनी नौसेना उसके बंदरगाह में रहें। इस संबंध में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार ने खुलासा किया कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर चीन को ग्वादर बंदरगाह में अपनी नौसेना के लिए शिपयार्ड के निर्माण का अनुरोध किया था।

ग्वादर बंदरगाह से तीन महत्वपूर्ण वाणिज्यिक क्षेत्रों पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में पहुँचना बहुत आसान हैं। चीन द्वारा ग्वादर को मध्य एशियाई क्षेत्र से निकलने वाले व्यापार और ऊर्जा गालियारे के लिए टर्मिनल पाईंट बनाया जा सकता हैं।[17] ग्वादर बंदरगाह चीन को सामरिक और भू–राजनीतिक लाभ प्रदान करेगा जिसमें पहला, चीन के कच्चे तेल की 60 प्रतिशत आपूर्ति इसी सामुद्रिक मार्ग से होती हैं जिसमें अधिक समय और धन लगता हैं जो अब ग्वादर बंदरगाह के कारण चीन के लाखों डॉलर और समय बच जायेगा। यह चीन की मलक्का जलडमरूमध्य पर निर्भरता को कम करेगा।

दूसरा, एशिया–प्रशांत और ग्वादर बंदरगाह में अमेरिका की उपस्थिति से चीन को काफी आर्थिक और सामरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हैं। ग्वादर बंदरगाह का संचालन चीन के पास होने से वह भारतीय और अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। ग्वादर बंदरगाह चीन के हाथों में आने से हिंद महासागर, विशेष रूप से भारत और अमेरिका प्रमुख हितधारकों के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। ग्वादर में चीन की उपस्थिति भारत और अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए हानिकारक हैं।

तीसरा, अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैन्यबलों को वापस बुलाने की घोषणा कर दी हैं। इस प्रकार अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों में व्यापार करने का मार्ग प्रशस्त हो गया हैं, जिस कारण चीन ने ग्वादर को विकसित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया हैं। चीन का उद्देश्य पश्चिम एशियाई देशों विशेषकर ईरान से तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान को पाईपलाईन गलियारे के रूप में उपयोग करने का हैं। चीन ने 7.6 अरब डॉलर की ईरान–पाकिस्तान गैस पाईपलाईन में रूचि दिखाई हैं। CPEC पाकिस्तान को चीन के लिए मध्य एशियाई देशों और अफगानिस्तान के साथ बातचीत का विस्तार करने में सक्षम बनायेगा।[18]

जैसा कि हमें ज्ञात है कि तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत के बीच तापी गैस पाईपलाईन पर समझौता हुआ हैं। यह पाईपलाईन मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाली पाईपलाईन होगी। इसके संदर्भ में भारत को यह डर हैं कि पाकिस्तान न केवल इस क्षेत्र से गुजरने वाली तेल आपूर्ति पर प्रभाव डालेगा बल्कि भारत की तेल और गैस आपूर्ति को भी रोक सकता हैं।

CPEC में चीन के समस्याएं

भारतीय विवादित क्षेत्र (गिल्गित–बाल्टिस्तान) से गुजरने के कारण भारत CPEC का विरोध कर रहा हैं। भारतीय विरोध के संबंध में चीनी विद्वानों का मत हैं कि वह अपने वन बेल्ट वन रोड़ के सपने को पूरा करने के लिए भारत–पाकिस्तान के विवादों के हल होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते।[19] चीनी विद्वानों के अनुसार चीन का ध्यान इस परियोजना के द्वारा आर्थिक विकास और रचनात्मक जुड़ाव से हैं ना कि भारत को घेरने के लिए हैं।

चीन अगर भारत को CPEC में शामिल करने में असफल होता हैं तो यह चीन के लिए अधिक चिंता का विषय होगा क्योंकि भारत CPEC के भारतीय विवादित क्षेत्र से निकलने के कारण इसे अपनी संप्रभुता पर आक्रमण मानेगा और विश्व के विभिन्न मंचों पर चीन की आक्रमणकारी नीतियों पर प्रहार करेगा। भारत के विरोध के कारण चीन को CPEC के लिए वैश्विक समर्थन प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न होगी।

चीन यदि भारतीय हिमालय क्षेत्र में घुसपैठ करना बंद कर दे, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् हेतु और एन.एस.जी. के मुद्दे पर भारत का समर्थन करें, अरूणाचल प्रदेश में भारत की संप्रभुता को मानें तथा मसूद अजहर के लिए वीटो का प्रयोग ना करें तो शायद

भारत इस परियोजना का हिस्सा बनने के संबंध में विचार कर सकता हैं।[20]

पाकिस्तान के आंतरिक हालात भी चीन के लिए चिंता का विषय हैं। यदि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पर पाकिस्तान नियंत्रण नहीं कर पायेगा तो यह चीनी हितों को झटका होगा। यह भी हो सकता हैं की अपनी विस्तारवादी नीति के चलते इस परियोजना की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी सेना को दे दी। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान एक गंभीर संकट में फंस जायेगा जिससे पाकिस्तान के टूटने की संभावनाओं को बल मिलेगा।

निष्कर्ष

21 वी सदी भारत और चीन की हैं, दोनों ही देश विश्व की उभरते हुई शक्तियां हैं। दक्षिण एशिया में भारत ही एक ऐसा देश हैं जो चीन को चुनौती देता हैं। भारत और चीन के अनसुलझे आपसी मुद्दें और इस परियोजना का भारतीय विवादित क्षेत्र से गुजरना भारत को CPEC का हिस्सा बनने से रोकने के साथ–साथ ऐसे सभी अच्छे संबंधों के लिए सहयोग तथा आर्थिक एकीकरण की योजनाओं में बाधा हैं।

चीन और भारत जनसंख्या, अर्थव्यवस्था एवं आकार के मामले में लगभग समान हैं। यहीं समानता दोंनों देशों को नजदीक आने का अवसर प्रदान करती हैं। दोनों ही देश वर्तमान विश्व की प्रमुख अर्थव्यस्थाएं हैं। जहां एक ओर चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी हैं वहीं भारत की विकास दर चीन की तुलना में अधिक होने के साथ ही एशिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था हैं। दोनों ही देश वर्तमान में विश्व के लिए दो महत्वपूर्ण बाजार तथा भविष्य की महान शक्तियां हैं।

भारत और पाकिस्तान के संबंधों की जटिलता दक्षिण एशिया की स्थिरता में सबसे बड़ी बाधक हैं। CPEC के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाये तो सक्षम पाकिस्तान भारत के लिए नई समस्याओं को उत्पन्न कर सकता हैं जिसमें दक्षिण एशिया के इन दोनों देशों में शस्त्रों की होड़ तथा कश्मीर मुद्दों पर टकराव की संभावना अधिक हैं। इन्हीं मुद्दों पर भारत को दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयास करने होंगे जिससे क्षेत्र में शांति और संतुलन बना रहे।

CPEC ने दक्षिण एशिया में दो ध्रुवों का निर्माण कर दिया हैं, जिसमें पहला हैं चीन–पाकिस्तान और दूसरा अमेरिका–भारत। इस टकराव की स्थिति में दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता संभव नहीं हैं। दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता तथा शंति हेतु चीन–भारत–पाकिस्तान को साथ आना होगा। इसके लिए इन तीनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को पारस्परिक विश्वास, सहयोग और समझ को विकसित करना होगा। इस हेतु चीन और पाकिस्तान को ईमानदारी के साथ भारत को CPEC में शामिल करना होगा, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता संभव हो सकें।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *https://sdpi.org/publications/files/China-Pakistan-Economic-Corridor-(Shakeel-Ahmad-Ramay).pdf*
2. *Ministry of Foreign Affairs, Government of Pakistan 2013.*
3. *Andrew Small "The China Pakistan Axis: Asia's New Geopolitics" Vintage Books, 2015.*
4. *Urooj Riz "CPEC: China Pakistan Economic Corridor" PI Publishers, 2017*
5. *Archana Rathore "China Pakistan Economic Corridor (CPEC)" Bane or Boom Lenin Media Pvt. Ltd., 2017.*
6. *Shanghai Institutes for International Studies, Shanghai, 15 November 2016 on 'China-India relations'.*
7. *Baqir Sajjad Syed, 'China to Build Four Submarines in Karachi', Dawn, 7 October 2015.*
8. *Koh Swee Lean Collin, 'China and Pakistan Join Forces under the Sea', The National Interest, 7 January 2016.*
9. *Press Trust of India, "Double Standards in Dealing with Terror Is Dangerous: Sushma Swaraj," The Indian Express, April 18, 2016.*
10. *Varghese K. George and Atul Aneja, "U.S. Backs, but China Opposes India's NSG Bid," The Hindu, May 15, 2016,*
11. *Ibid*
12. *Dipanjan Roy Chaudhury, "India's Trade with Pakistan May Get a Boost by Nawaz Sharif Government following PM Modi's Fresh Initiative," The Economic Times, December 28, 2015.*
13. *http://www.claws.in/images/events/pdf/2005908665_RegionalDiplomacySeminarReport-Corrected.pdf*
14. *Senior U.S. Government Official "B" in discussion with the author, Washington D.C., January 2015.*
15. *"Naval Base in Gwadar," The News, May 21, 2016.*
16. *The Hindu, 23, August, 2017.*
17. *Iqra Shanaz, "Gwadar Port: Challenges and Opportunities," INCPak, June 18, 2015.*
18. *Syed Fazl-e-Haider, "Restive Region may yet Spell Trouble for China's Gwadar Plan," The National, June 18, 2015.*
19. *The Economic Times, 31 August 2016.*
20. *The Indian Express, June 13, 2017, p.15.*